

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा—भारत की एकता हमारी शक्ति, अखण्डता हमारी जिम्मेदारी

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस केवल एक स्मृति दिवस नहीं, बल्कि वर्ष 1947 की भीषण त्रासदी से सीख लेने का अवसर है। यह त्रासदी विश्व मानवता के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। विभाजन के कारण करोड़ों हिंदुओं को अपनी मातृभूमि और जन्मभूमि से विस्थापित होना पड़ा, जबकि लाखों हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन नागरिकों को इसकी पीड़ा झेलनी पड़ी।मुख्यमंत्री शुक्रवार को लोक भवन में विभाजन विभीषिका त्रासदी पर आधारित प्रदर्शनी, लाइव पेंटिंग और लघु फिल्म का अवलोकन करने के बाद आयोजित कार्यक्रम की संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विभाजन से विस्थापित परिवारों के सदस्यों को सम्मानित किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने जीपीओ स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल पार्क में सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और प्रतिमा स्थल से लोक भवन तक मौन पदयात्रा में हिस्सा लिया।मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम के सभी क्रांतिकारियों



और बलिदानियों को नमन करते हुए कहा कि विभाजन के समय विस्थापित परिवारों की पीड़ा को सुनने वाला कोई नहीं था। यह आत्ममंथन जरूरी है कि विभाजन की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। उन्होंने कहा कि इतिहास केवल परीक्षा का विषय नहीं, बल्कि गौरवशाली क्षणों

से प्रेरणा लेने और अतीत की गलतियों का परिमार्जन करने का माध्यम है।योगी ने कहा कि भारत सभी धन-धान्य और वैभव से परिपूर्ण देश था। 16वीं-17वीं शताब्दी में विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 24 से 25 प्रतिशत तक बताई जाती थी। इसके बावजूद भारत गुलाम हुआ। उन्होंने कहा कि आपसी

अंतर्विरोध और षड्यंत्र इसके प्रमुख कारण रहे। जाति, क्षेत्र और भाषा के आधार पर पैदा किए गए मतभेदों ने देश को कमजोर किया और बाहरी ताकतों को षड्यंत्र करने का अवसर दिया।उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और वीर सावरकर जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया। इसके बावजूद देश को विभाजन की पीड़ा झेलनी पड़ी और इसकी कीमत आज भी आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवाद और उग्रवाद के रूप में चुकानी पड़ रही है।मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन घटनाओं की ओर भी ध्यान आकर्षित करता है, जिन पर लंबे समय तक चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जिन क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, उन्हें भुला दिया गया, जबकि सत्ता और स्वार्थ के लिए देश के विभाजन में भूमिका निभाने वाले

लोग सत्ता में स्थापित हो गए। उन्होंने वर्तमान और भावी पीढ़ी से इतिहास को इन घटनाओं से सीख लेने का आह्वान किया।नागरिकता संशोधन कानून का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से उल्पीड़न के कारण भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। उन्होंने कहा कि इस कानून में किसी की जमीन या संपत्ति छीनने का प्रावधान नहीं था, इसके बावजूद कई स्थानों पर विरोध और हिंसा के प्रयास हुए। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, मेरठ, संभल, अलीगढ़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर सहित कई स्थानों पर आगजनी के प्रयास हुए।उन्होंने कहा कि भारत की एकता और अखंडता प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। व्यक्तिगत स्तर पर किसी की पहचान पंजाबी, बंगाली, मराठी, तमिल, कन्नड़ या मलयाली हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी पहचान भारतीय की होनी चाहिए।

स्वतंत्रता दिवस पर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं

आर्यावर्त क्रांति व्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए सभी के सुख, समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना की है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जारी संदेश में उन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले ज्ञात-अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों और वीर शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन किया।

पर्यटन मंत्री ने कहा कि देश की स्वतंत्रता असंख्य वीरों के त्याग, संघर्ष और बलिदान का परिणाम है। आजादी के लिए अनेक वीरों ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, जिसके फलस्वरूप देशवासियों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त हमें स्वतंत्रता संग्राम के उन ज्ञात और अज्ञात शहीदों को स्मरण करने तथा उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है।उन्होंने कहा

विभाजन की पीड़ा और विस्थापन के संघर्ष को किया याद, बीबीएयू में मनाया गया विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस

लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय में शुक्रवार को आजादी का अमृत महोत्सव समिति की ओर से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राज कुमार मिश्र ने की। इस दौरान विभाजन के समय विस्थापित हुए लोगों की पीड़ा, संघर्ष और उनके पुनर्वास की कठिन परिस्थितियों को याद करते हुए युवा पीढ़ी को इतिहास से सीख लेने और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का संदेश दिया गया। कुलपति प्रो. राज कुमार मिश्र ने कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह देश के उस कठिन दौर की याद दिलाता है, जब स्वतंत्रता के लिए असंख्य लोगों ने अपना सर्वस्व न्योछावर किया।

अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, परमहंस रामचंद्र दास महाराज की 23वीं पुण्यतिथि पर अर्पित की श्रद्धांजलि, रामलला के दर्शन कर संतों का लिया आशीर्वाद

लखनऊ। मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अपने दौरे की शुरुआत रामकथा पार्क स्थित ब्रह्मलीन परमहंस रामचंद्र दास महाराज के समाधि स्थल पर पहुंचकर पुष्पार्चन से की। श्रीराम जन्मभूमि न्यास के प्रथम अध्यक्ष रहे परमहंस रामचंद्र दास महाराज की 23वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संत-महत और श्रद्धालु मौजूद रहे।परमहंस रामचंद्र दास महाराज का अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा था। गोरक्षपीठ के ब्रह्मलीन महंत अवेदनाथ के साथ वह रामजन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख संतों में शामिल रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी परमहंस रामचंद्र दास महाराज से आत्मीय संबंध रहा है। उनकी पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की मौजूदगी से संत समाज में विशेष उत्साह देखने को मिला। समाधि स्थल पर मुख्यमंत्री ने विधिवत पूजा-अर्चना कर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके योगदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया। संत-महंतों ने भी ब्रह्मलीन संत को श्रद्धांजलि अर्पित की।समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी पहुंचे। यहां उन्होंने बजरंगबली के दर्शन-पूजन किए और प्रदेश तथा देश की सुख-समृद्धि की कामना की। हनुमानगढ़ी में दर्शन-पूजन के बाद मुख्यमंत्री इमली बाग पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्गीय महंत संत रामदास को श्रद्धांजलि अर्पित की।इसके बाद मुख्यमंत्री श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर पहुंचे और रामलला के दर्शन-पूजन किए। उन्होंने मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना कर रामलला का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री के अयोध्या आगमन को देखते हुए मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह रहा।रामलला के दर्शन के बाद मुख्यमंत्री दिगांबर अखाड़ा पहुंचे, जहां ब्रह्मलीन परमहंस रामचंद्र दास महाराज के 23वें पुण्य स्मृति महोत्सव में शामिल हुए। यहां उन्होंने संत-महंतों से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में संत समाज के अनेक प्रमुख संतों की मौजूदगी रही। मुख्यमंत्री ने संतों के साथ धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर भी संवाद किया।मुख्यमंत्री अपने अयोध्या दौरे के दौरान रायगंज स्थित संत रविदास मंदिर भी पहुंचे। उन्होंने संत रविदास को नमन किया और मंदिर के स्वर्गीय महंत पूंय्य बनवारी पति ब्रह्मचारी को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं और संत समाज ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।मुख्यमंत्री के पूरे अयोध्या दौरे में धार्मिक आस्था और संत परंपरा के प्रति सम्मान का भाव देखने को मिला। परमहंस रामचंद्र दास महाराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन, श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के पूजन और संत रविदास मंदिर में श्रद्धांजलि अर्पित कर अयोध्या के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर अपनी आस्था प्रकट की। उनके दौरे के दौरान संतों और श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह नजर आया।

स्वतंत्रता दिवस पर बीएसएनएल का बड़ा ऑफर, एकरुपये में 24 दिन की सेवा और 2,399 रुपये के रिचार्ज पर 47 दिन अतिरिक्त वैधता

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने अपने ग्राहकों के लिए कई विशेष प्रचारात्मक योजनाएं शुरू की हैं। उत्तर प्रदेश (पूर्व) परिमंडल की ओर से जारी जानकारी के अनुसार मोबाइल और फाइबर ब्रॉडबैंड ग्राहकों को किकारती दरों पर अतिरिक्त सुविधाएं और लंबी वैधता का लाभ दिया जा रहा है। बीएसएनएल ने इस अवसर पर कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन, स्वदेशी 4जी नेटवर्क के विस्तार और दूरदराज क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी।बीएसएनएल के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का कुल कारोबार 21,462 करोड़ रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 2,324

अमौसी मेट्रो स्टेशन के पास अज्ञात पिकअप की टक्कर से युवक की मौत, सीसीटीवी से चालक की तलाश

लखनऊ। सरोजनीनगर थाना क्षेत्र में अमौसी मेट्रो स्टेशन के पास गुरुवार रात हुए सड़क हादसे में 33 वर्षीय युवक की मौत हो गई। बताया गया कि युवक सीए फर्म में काम करके बाइक से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान मदौना मस्जिद के पास एक अज्ञात पिकअप वाहन ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उपचार के लिए ले जाते समय उसकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान रजनीकांत तिवारी पुत्र विजय नारायण तिवारी, निवासी बगही, थाना केरकत, जनपद जौनपुर, उम्र करीब 33 वर्ष, के रूप में हुई है। वह वर्तमान में दरोगा खेड़ा, थाना सरोजनीनगर, लखनऊ में रह रहे थे। 13 अगस्त की रात करीब 8:30 बजे वह पत्रकारपुरम, गोमतीनगर स्थित एक सीए फर्म में काम करने के बाद घर लौट रहे थे।

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। प्रदेश के ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन, उत्तर प्रदेश शासन और पीडी हिंदुजा हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को हिंदुजा मोबाइल हेल्थ यूनिट्स की शुरुआत की गई। शहीद पथ स्थित डॉ. राम मोहनर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के मातृ एवं शिशु रेफरल अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मोबाइल हेल्थ यूनिट्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने ‘सेविंग लाइव्स एंड बिल्डिंग ए हेल्थियर भारत’ राष्ट्रीय अभियान की भी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऐसे ग्रामीण और दूरदराज



क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जहां लोगों को सामान्य जांच और उपचार के लिए भी दूर स्थित अस्पतालों तक जाना पड़ता है। मोबाइल हेल्थ यूनिट्स के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के घर-द्वार के करीब पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।

ब्रजेश पाठक ने कहा कि मोबाइल हेल्थ यूनिट्स के जरिए लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य जांच,

विभिन्न बीमारियों की पहचान और आवश्यक चिकित्सा परामर्श उपलब्ध करایा जाएगा। इन यूनिट्स का उद्देश्य उन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच अपेक्षाकृत कठिन है। इससे ग्रामीण आबादी को समय पर जांच कराने और बीमारी की शुरुआती अवस्था में ही उपचार प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

जनसेवा केंद्र संचालक से लूट का खुलासा, चार शातिर गिरफ्तार, डेढ़ लाख नकद समेत लूट की रकम से खरीदे दो मोबाइल बरामद

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। गोसाईगंज थाना क्षेत्र में जनसेवा केंद्र संचालक से हुई लूट की घटना का सर्विलांस सेल जौन दक्षिणी और गोसाईगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने खुलासा करते हुए चार शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 1.50 लाख रुपये नकद, लूट की रकम से खरीदे गए आईफोन 12 प्रो और ओपो एफ-33 मोबाइल फोन, वादी के आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल तथा लकड़ी का डंडा बरामद किया है। बरामद दोनों मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत करीब 70 हजार रुपये बताई गई है।पुलिस के अनुसार, 6 अगस्त 2026 को राहुल कुमार पुत्र काशीराम निवासी महारा खुर्द, थाना गोसाईगंज अपनी दुकान बंद कर घर जा रहे थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार



बदमाशों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और डंडे से हमला कर गिराने के बाद उनका बैग लूटकर फरार हो गए। मामले में राहुल कुमार की तहरीर पर गोसाईगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।घटना की गंभीरता से लेते हुए पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के निर्देश पर पांच पुलिस टीमों का गठन किया गया। जांच में सर्विलांस सेल को भी लगाया गया। पुलिस टीमों ने घटना के

आसपास के मागों पर लगे करीब 150 से 200 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाए। लगातार की गई जांच के बाद पुलिस को बदमाशों के बारे में दुकान बंद करने के बाद अकेले घर जाते हैं। उनके पास अक्सर नकदी रहती थी। इसी जानकारी के आधार पर आरोपियों ने राहुल की रेकी की और वारदात को अंजाम देने की

योजना बनाई।आरोपियों के मुताबिक घटना वाले दिन राहुल के दुकान से निकलने की सूचना मिलने के बाद सभी लोग रास्ते में घात लगाकर बैठ गए। जैसे ही वह महारुक्ला से महारा खुर्द की ओर जाने वाली सड़क पर पहुंचे, आरोपियों ने डंडे से हमला कर उन्हें गिरा दिया और बैग लेकर फरार हो गए। लूट की रकम में से आरोपियों ने मोबाइल फोन खरीदे और अलग-अलग होटलों में पार्टी की।पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1.50 लाख रुपये नकद, आईफोन 12 प्रो, ओपो एफ-33, वादी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल लकड़ी का डंडा भी बरामद किया है।जांच के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त शिवा का आपराधिक इतिहास भी सामने आया। उसके खिलाफ थाना मोहनलालगंज

की स्वतंत्रता दिवस केवल राष्ट्रीय उत्सव मनाने का अवसर नहीं, बल्कि देश के प्रति अपने दायित्वों और जिम्मेदारियों को याद करने का भी दिन है। स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस भारत का सपना देखा था, उसे साकार करने की जिम्मेदारी आज प्रत्येक नागरिक की है। देश की प्रगति और समृद्धि में हर नागरिक का योगदान महत्वपूर्ण है।जयवीर सिंह ने प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि वे 15 अगस्त के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक विकसित भारत और विश्वगुरु बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा, लगन और समर्पण के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति में समाज के प्रत्येक वर्ग की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र को महान बनाने में उसके नागरिकों की

भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। नागरिक अपने-अपने क्षेत्र में ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और जिम्मेदारी के साथ कार्य करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। देश की प्रगति केवल सरकार के प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।पर्यटन मंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के वीर सपुतों ने जिस भारत के निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित किया, उस नए भारत के निर्माण की जिम्मेदारी आज हम सभी के कंधों पर है। इसलिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ-साथ उनके सपनों और संकल्पों को पूरा करने के लिए स्वयं को समर्पित करने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने प्रदेशवासियों से देश की एकता, अखंडता और विकास के लिए मिलकर कार्य करने की अपील की।

पूर्व पत्नी ने तवे से किया हमला, घायल पति की इलाज के दौरान मौत; पुलिस हिरासत में आरोपी महिला

लखनऊ। जानकीपुरम थाना क्षेत्र में पूर्व पति-पत्नी के बीच विवाद के दौरान हुई मारपीट में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपी के विवाद के दौरान पूर्व पत्नी ने तवे से उसके सिर पर प्रहार कर दिया। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी पूर्व पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार 13 अगस्त 2026 को थाना जानकीपुरम पुलिस की सूचना मिली कि आशीष सोनी, निवासी आशिखाना, लखनऊ अपनी पूर्व पत्नी तपस्या सिंह के कौशल्या गार्डन स्थित घर पहुंचा था। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद के दौरान तपस्या सिंह द्वारा आशीष सोनी के सिर पर तवे से प्रहार किए जाने की बात सामने आई है।सिर पर गंभीर चोट लगने के बाद आशीष सोनी को तत्काल उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर, जानकीपुरम ले जाया गया। हालत गंभीर होने के कारण चिकित्सकों ने उसे बेहतर उपचार के लिए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी रेफर कर दिया। उपचार के दौरान आशीष सोनी की मौत हो गई।घटना की सूचना मिलते ही जानकीपुरम थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। मृतक के शव के संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के लिए पुलिस टीम केजीएमयू भेजी गई है।पुलिस ने घटना के संबंध में मृतक की पूर्व पत्नी तपस्या सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

ओवरटेक को लेकर दो पक्षों में कहासुनी, सोशल मीडिया पर फायरिंग की खबर से मचा हड़कंप; पुलिस जांच में नहीं हुई पुष्टि

लखनऊ। ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में 13 अगस्त की रात वाहन ओवरटेक करने को लेकर बाइक और स्कॉपियों-पन सवार लोगों के बीच कहासुनी और विवाद हो गया। घटना की सूचना मिलते ही गश्त कर रही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। इस दौरान सोशल मीडिया पर विवाद के दौरान फायरिंग किए जाने की खबर प्रसारित हुई, लेकिन पुलिस की मौके पर जांच और पूछताछ में फायरिंग की घटना की पुष्टि नहीं हो सकी।पुलिस के अनुसार 13 अगस्त 2026 को रात करीब 11 बजे गोल्ड होटल के पास बाइक संख्या यूपी 32 एचएक्स 9102 और स्कॉपियों-पन संख्या यूपी 32 पीएक्स 3334 सवार लोगों के बीच वाहन को ओवरटेक करने को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने की सूचना पर गश्त कर रहे पुलिसकर्मी तत्काल मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को शांत कराया।पुलिस के मौके पर पहुंचने के दौरान स्कॉपियों-पन सवार एक व्यक्ति वहां से चला गया। मौके पर मौजूद अन्य लोगों को शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से चौकी भूहर लाया गया। पुलिस ने पूछताछ के दौरान उनकी पहचान शुभम सिंह पुत्र रणवीर सिंह निवासी मवई खुर्द, थाना माल, मनीष सिंह चौहान पुत्र छुटक सिंह निवासी गोपरामऊ, थाना माल और प्रमोद सिंह यादव पुत्र स्वर्गीय दया प्रसाद निवासी ग्राम पलहरी, थाना सेरपुर, लखनऊ के रूप में की।घटना के बाद सोशल मीडिया पर विवाद के दौरान फायरिंग किए जाने की खबर प्रसारित होने लगी।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 14 से 24 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन, प्रदेश में छह परियोजनाओं के लिए मिलेगा लाभ

लखनऊ. (आरएसएस) । उत्तर प्रदेश के मत्स्य विकास मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद ने शुक्रवार को मत्स्य निदेशालय में आयोजित कार्यक्रम में बताया कि भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 से संवर्धित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) की अवधि सितंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है। योजना के अंगरंग उपलब्ध अवधि लक्ष्यों के सापेक्ष पात्र लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए विभागीय पोर्टल पर 14 अगस्त से 24 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।मत्स्य विकास मंत्री ने बताया कि योजना के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं का विस्तृत विवरण, इकाई लागत, पात्रता, आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन के साथ लगाए जाने वाले आवश्यक अभिलेख और अन्य संबंधित जानकारी विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध है। इसकृए एवं पात्र लाभार्थी निर्धारित अवधि के भीतर विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।उन्होंने बताया कि प्रदेश में मत्स्य विकास की व्यापक संभावनाओं को देखते हुए उपलब्ध जल संसाधनों का वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण से समुचित उपयोग सुनिश्चित करने और मत्स्य पालकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।



संसदीय समिति की रिपोर्ट से उठते सवाल- प्राइवेट अस्पतालों और स्कूलों की लूट पर कब लगेगी लगाम?

पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में प्राइवेट यानी निजी अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजों की बाढ़ सी आ गई है। देश के राज्य और जिले तो छोड़िए , अब तो छोटे-छोटे शहरों में भी खुलते जा रहे नर्सिंग होम और स्कूल लोगों की जेब काटने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। देश का गरीब तबका तो छोड़िए, मध्यम आय और उच्च मध्यम आय की कैटेगरी में आने वाले लोग भी इनकी लूट से परेशान होते जा रहे हैं। ऐसे में प्राइवेट अस्पतालों को लेकर आई संसदीय समिति की एक रिपोर्ट ने फिर से इस धाव को ताजा कर दिया है। एक बार फिर से वही पुराना सवाल उठ कर खड़ा हो गया है कि खुली लूट का अड्डा बन चुके प्राइवेट अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजों की मनमानी पर आखिर कब लगाम लगेगी ? देश के प्राइवेट अस्पताल, भर्ती होने वाले मरीजों/ उनके परिजनों से कमरे का जो किराया वसूलते है, यह उसी इलाके के महंगे होटलों से भी कई गुना ज्यादा होता है। ध्यान दीजिएगा, इलाज के नाम पर जो बाकी चार्ज लिए जाते हैं वो कमरे के चार्ज में अलग से जोड़ा जाता है। यह सारे खुलासे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट से हुए हैं। समिति की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी अस्पतालों में इलाज का खर्च औसतन ६,६३१ रुपए है जबकि प्राइवेट अस्पतालों में यही खर्च साढ़े सात गुने से भी ज्यादा (५०,५०८ रुपए) है। इलाज के नाम पर भी अनाप-शनाप वसूली की जाती है। बिल में पारदर्शिता नहीं होती है, गंभीर इलाज या सर्जरी से पहले मरीज को फाइनल खर्च के अस्टिमेट नहीं बताया जाता है। नतीजा प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी बेलगाम होती जा रही है और जिसकी जो मर्जी वो वसूल रहा है। मुंबई के नानावटी अस्पताल में कमरे का चार्ज ६ से १२ हजार रुपए प्रतिदिन है जबकि उसी इलाके के ३ स्टार होटल में कमरे कमरे का चार्ज २५०० से लेकर ४५०० रुपए के बीच ही है। दिल्ली के साकेत में स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती मरीज से अस्पताल वाले ७-११ हजार रुपए प्रतिदिन कमरे का चार्ज वसूलते है जबकि अस्पताल के पास ही स्थित होटल में आपको २१०० से ३५०० रुपए प्रतिदिन के आधार पर बढ़िया कमरा मिल सकता है। यही हाल देश के ज्यादातर शहरों में प्राइवेट अस्पतालों का है।

समिति ने सरकार को कुछ सुझाव देते हुए यह सिफारिश की है कि, प्राइवेट अस्पताल के कमरे का किराया ३ स्टार होटल के किराए से अधिक नहीं होनी चाहिए। भर्ती से पहले अस्पताल को इलाज का पूरा खर्च स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। सर्जरी और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए फिक्स रेट तय होना चाहिए और उसमें सभी खर्चे शामिल होने चाहिए। इसके अलावा भी संसदीय समिति ने कई महत्वपूर्ण सिफारिश करते हुए सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाए है। समिति ने स्पष्ट तौर पर सरकार को सरकारी अस्पतालों में बेड और विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने को कहा है। हालांकि यह सब जानते हैं कि सरकार ऐसा करेगी नहीं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि स्वास्थ्य मंत्रालय समिति की रिपोर्ट की आड़ लेकर कहीं वैसा ही खेल न कर दें जैसा कि CGHS चार्ज के मामले में किया गया है। सरकार को यह याद दिलाना बेहद जरूरी है कि दिल्ली या मुंबई के महंगे अस्पतालों में इलाज का खर्च इन शहरों के हिसाब से है वहीं देश के दूर-दराज इलाकों में इलाज का खर्च उस इलाके के आधार पर है। डर इस बात का है कि कहीं CGHS में जो गलतियां की गई है,उसी तरह की गलती को इस मामले में दोहराते हुए दिल्ली या मुंबई के आधार पर इलाज और सर्जरी का फिक्स रेट पूरे देश के लिए न तय कर दिया जाए। ऐसे हालात में दूर-दराज के इलाकों में चलने वाले प्राइवेट अस्पताल सरकारी आदेश का हवाला देते हुए कई गुना पैसा वसूलना शुरू कर देंगे। सरकार , सरकार के मंत्री और अधिकारियों को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। जब भी प्राइवेट अस्पतालों की खुली लूट का जिक्र आता है तो आप इससे स्कूलों और कॉलेजों को अलग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से एक छोटे नर्सिंग होम को बड़ा और भव्य अस्पताल बनने में देर नहीं लगती, उसी तरह से स्कूल और कॉलेजों की बिल्डिंग भी साल दर साल भव्य से भव्यतम होती चली जाती है। फीस, कितनेबैं, ड्रेस और बाकी खर्चों की मनमानी के बारे में तो सबको मालूम है। इसलिए यहां पर हम सिर्फ कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहेंगे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में स्थित एक मेडिकल कॉलेज से MBBS करने की कुल लागत सवा से डेढ़ करोड़ रुपए के बीच आती है। मिडिल क्लास तो छोड़िए , हाई इनकम ग्रुप में आने वाले लोगों के लिए भी अब अपने बच्चों को MBBS करवा पाना आसान नहीं रहा है। आजकल प्राइवेट स्कूलों में लूट का एक जरिया स्मार्ट बोर्ड यानी स्मार्ट क्लासेस भी बन चुका है।

व्यंग्य

लाभ उठाने की रणनीति नाकाम



जिस समय देश में 'विश्व गुरु' बनने की खुशफहमी का आलम था, असल में भारत सरकार अवसरों का लाभ उठाने की कारगर रणनीति बनाने में नाकाम रही। दो बड़े थिंक टैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं।

दो थिंक टैंक इस समान निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि २०१८ के बाद वैश्विक समीकरणों में शुरू हुए तेज बदलाव से जो अवसर सामने आया, भारत उसका लाभ उठाने में विफल रहा। दरअसल, यह उस दौर की कथा है, जिसमें भारत के 'विश्व गुरु' बनने की कहानियों पर करोड़ों देशवासी यकीन किए हुए थे। लेकिन जिस समय ऐसी खुशफहमी का आलम था, असल में भारत सरकार अवसरों का लाभ उठाने की कारगर रणनीति बनाने में नाकाम रही। न्यूयॉर्क स्थित थिंक टैंक रोडियम ग्रुप ने 'क्या भारत अंततः अपनी मैनुफैक्चरिंग महत्वाकांक्षाओं को हासिल कर सकेगा'- शीर्षक से जारी अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि २०१८ में जब अमेरिका और चीन में व्यापार जंग शुरू हुई, तो यह आम धारणा बनी कि चूँकि कंपनियां अपना कारोबार चीन से निकालकर दूसरे देशों में ले जाएंगी, तो भारत को इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

विवतनाम और मेक्सिको ने इस मामले में कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है। अमेरिका को चीन के निर्यात में आई गिरावट से खाली हुई जगह को उन्होंने प्रभावी ढंग से भरा। इससे इन देशों के मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र में ज्यादा मूल्य (वैल्यू) जुड़ा, जबकि भारत इस मामले में काफी पीछे रह गया है। रणनीतिक मामलों में ऐसे ही निष्कर्ष पर ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट पहुंचा है। उसके 'एशिया पावर इंडेक्स' के मुताबिक भारत अपनी विशाल क्षमताओं और संसाधनों के बावजूद एशिया में प्रभावशाली शक्ति या क्षेत्रीय 'एंकर' (स्थिरता प्रदान करने वाली प्रमुख ताकत) नहीं बन पा रहा है।

इंस्टीट्यूट के मुताबिक भारत के पास जितनी क्षमता, जनसंख्या, और संसाधन हैं, उनकी तुलना में उसका वास्तविक क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव बहुत कम है। भारत का क्षेत्रीय रक्षा गठबंधनों और व्यापारिक साझेदारियों में प्रभाव अन्य प्रमुख शक्तियों की तुलना में सीमित है, जिससे यह अपनी क्षमता का पूरा लाभ नहीं उठा पाया है। चीन से परिचम की प्रतिस्पर्धा के मद्देनजर भारत से हमदर्दी रखने वाली विदेशी संस्थाएं ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचती हैं, तो उस पर भारतवासियों को ध्यान देना चाहिए। जब जवाबदेही का मुद्दा उठा है, इन नाकामियों के लिए कौन उत्तरदायी है, ये सवाल भी जरूर पूछा जाना चाहिए।

समावेशी, पारदर्शी सरकारी खरीद का बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जेम

पीयूष गोयल

सरकारी खरीद के लिए सरकार का ई-मार्केटप्लेस (जेम) वैश्विक स्तर पर एक पारदर्शी, समावेशी और कुशल प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है, जो १.३७ लाख सरकारी खरीदारों को २५ लाख विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं से जोड़ता है।

जेम प्लेटफार्म की विशेषता है कि यह खरीद से जुड़ी सभी प्रमुख गतिविधियों को एक बड़े डिजिटल मार्केटप्लेस में एकीकृत करता है। यह वैश्विक सर्वोत्तम तौर-तरीकों को सरकार के समावेशी विकास के साथ जोड़ता है, जिससे यह पीएम मोदी के विकसित भारत २०४७ के विजन को आगे बढ़ाने वाला इंजन बन जाता है।

२०१६ में पीएम द्वारा इस परिवर्तनकारी डिजिटल पहल की शुरुआत के एक दशक में, जेम ने भ्रष्टाचार को मिटाकर और स्टार्टअप, एमएसएमई, महिला उद्यमियों और छोटे शहरों के व्यवसायों को बढ़ावा देकर, सरकारी खरीद में क्रांति ला दी है। उपयोगकर्ता-अनुकूल यह प्लेटफ़ॉर्म वास्तव में एक रत्न है, जिसने विवादित आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय की जगह ली है, जिसकी प्रणालियाँ अस्पष्ट और गैर-प्रतियस्धी थीं। इससे खरीदारी प्रणाली के केवल कुछ सुविधा-प्राप्त लोगों को ही अनुचित फ़ायदा मिलता था।

यह उचित है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का नया, आधुनिक कार्यालय, वाणिज्य भवन, उसी ज़मीन पर बना है, जहाँ कभी वह पुरानी और संदिग्ध प्रविष्टा वाली संस्था हुआ करती थी।

वाणिज्य और उद्योग के मंत्री के रूप में, मुझे गर्व है कि जेम, जिसे ९ अगस्त २०१६ को लॉन्च किया गया था, अपनी शानदार सेवा के दस साल पूरे कर रहा है। यह सिर्फ आंकड़ों का जश्न मनाने वाला पड़ाव नहीं है; बल्कि यह इस बात में एक बुनियादी और सफल बदलाव है कि कैसे सरकारी खरीद देश के निर्माण में योगदान देती है।

उत्पाद खोजने और बोली लगाने से लेकर अनुबंध देने और भुगतान करने तक, पूरी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर जेम ने मनमाने फैसलों को खत्म किया है, निष्पक्ष प्रतियस्धी को बढ़ावा दिया है और लोगों के भरोसे को मजबूत किया है। हर लेन-देन का एक डिजिटल रिकॉर्ड बनता है जिसकी जांच की जा सकती है; इससे जवाबदेही बढ़ती है और सरकारी खरीद के प्रति निष्ठा मजबूत होती है। जेम पीएम मोदी के व्यवसाय करने में आसानी मिशन का एक

ब्लॉग

खेल में अपनी प्रतिभा को पहचाने और भविष्य संवारेें

तेजबहादुर सिंह भुवाल

एक समय था जब यह माना जाता था कि केवल पढ़ाई-लिखाई ही उज्ज्वल भविष्य और अच्छी नौकरी का मार्ग है। इसी सोच को दशांते हुए कहा जाता था- 'पढ़ोगे-लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे-कूदोगे बनोगे खराब'। लेकिन आज का भारत इस धारणा को पूरी तरह बदल चुका है।

इसलिए आज के दौर में यह कहना उचित नहीं होगा कि केवल पढ़ाई-लिखाई ही सफलता का एकमात्र मार्ग है। यदि किसी में खेल के प्रति जुनून, अनुशासन और समर्पण है, तो वह खेलों के माध्यम से भी अपने सपनों को साकार कर सकता है। शिक्षा और खेल, दोनों मिलकर व्यक्तिगत का समग्र विकास करते हैं तथा जीवन में सफलता के नए द्वार खोलते हैं।

खेल केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह व्यक्तित्व निर्माण, आत्मविश्वास, अनुशासन और सफलता की ऐसी पाठशाला है, जहाँ से भविष्य के विजेता तैयार होते हैं। आज खेलों में करियर की असीम संभावनाएँ हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मान, रोजगार, आर्थिक सुरक्षा और वैश्विक पहचान मिल रही है। ऐसे समय में प्रत्येक युवा के लिए आवश्यक है कि वह अपनी खेल प्रतिभा को पहचाने और उसे सही दिशा देकर अपने भविष्य को संवारे।

हर बच्चे के भीतर कोई न कोई विशेष क्षमता होती है। किसी की गति उसे उत्कृष्ट धावक बनाती है तो किसी की फुर्ती कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, तीरंदाजी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल या अन्य खेलों में सफलता दिला सकती है। यदि प्रतिभा को समय पर प्रशिक्षण और अवसर मिले, तो वही खिलाड़ी प्रदेश और देश का गौरव बनाता है।

खेलों का सबसे बड़ा योगदान यह है कि वे जीवन के महत्वपूर्ण गुणों का विकास करते हैं। अनुशासन, धैर्य, नेतृत्व क्षमता, टीम भावना, समय प्रबंधन और संघर्ष का साहस खेल के मैदान में ही सीखा जाता है। यही गुण आगे चलकर जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की नींव रखते हैं।

छत्तीसगढ़ में खेलों को नया स्वरूप देने की दिशा में राज्य शासन ने उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने, ग्रामीण और जनजातीय अंचलों के युवाओं को अवसर उपलब्ध कराने तथा खेल संस्कृति को मजबूत करने के लिए अनेक पहल की जा रही हैं। प्रदेश में आधुनिक खेल अधीसंरचना का विकास, प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार, खेल अकादमियों को सुदृढ़ करना तथा विभिन्न स्तरों पर प्रतियोगिताओं का आयोजन इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इसी के साथ ही इस वर्ष से छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय खेलों इंडिया ट्राइबल गेम्स का सफल आयोजन किया गया है।

विशेष रूप से बस्तर ओलंपिक और सरगुजा



ओलंपिक जैसी अभिनव पहल ने खेलों को गाँव-गाँव तक पहुँचाया है। इन आयोजनों ने दूरस्थ वनांचलों और जनजातीय क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया है। परंपरागत खेलों के साथ आधुनिक खेलों को भी बढ़ावा देकर हजारों युवाओं, महिलाओं और बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला है। इन प्रतियोगिताओं ने यह साबित किया है कि अवसर मिलने पर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के खिलाड़ी अब राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचने की क्षमता रखते हैं।

इसके साथ ही विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं, ग्रामीण खेल आयोजनों, प्रतिभा खोज कार्यक्रमों तथा प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से नई प्रतिभाओं की पहचान की जा रही है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, सम्मान और विभिन्न सुविधाएँ उपलब्ध कराकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तर पर कई पुरस्कार प्रदान करती है। जिसमे गुंडाधुर सम्मान शामिल है। यह छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण के तहत दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। यह पुरस्कार बस्तर के वीर नायक गुंडाधुर की स्मृति में, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य के सर्वश्रेष्ठ

महत्वपूर्ण हिस्सा है। एकल डिजिटल विंडो, आसान पंजीकरण, मानकीकृत प्रक्रिया और नियमित नीतिगत सुधार - जैसे अमानत राशि को खत्म करना और लेन-देन शुल्क को युक्तिसंगत बनाना - के जरिये जेम ने भागीदार बनने की बाधाओं को काफी हद तक कम किया है, जिससे सरकारी खरीद तक पहुँच आसान हो गयी है। जेम ने आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उद्यमों को बढ़ावा देने के लक्ष्य को मजबूती से आगे बढ़ाया है। धरेलू निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं को प्राथमिकता देकर, इसने स्थानीय मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत किया है और देशी उत्पादन को प्रोत्साहित किया है।

पोर्टल पर दिया गया हर ऑर्डर भारत की निर्माण क्षमता और आर्थिक संप्रभुता में एक निवेश है। खास बात यह है कि जेम में मात्रा के आधार पर लगभग ६०८न ऑर्डर और सकल माल मूल्य (जीएमवी) में ४५न से ज्यादा की हिस्सेदारी सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) की है।

जेम, पीएम मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास' मिशन के अनुरूप समावेशी विकास का एक महत्वपूर्ण इंजन के रूप में सेवाएँ देता है। यह स्टार्टअप, छोटे व्यवसायों और महिलाओं द्वारा संचालित उद्यमों को बिना किसी बाधा या मध्यस्थ के सरकारी खरीदारों के सामने अपने उत्पादों और सेवाओं को आसान तरीके से पेश करने का मौका देता है। प्रवेश करने की बाधाओं को खत्म करके और सरकारी खरीद तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाकर, जेम ने पूरे देश के छोटे व्यवसायों को राष्ट्र-निर्माण में सक्रिय भागीदार बनने और उस व्यावसायिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सशक्त बनाया है, जिस पर कभी स्थापित कंपनियों का दबदबा हुआ करता था।

जेम के माध्यम से १२ लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उद्यमों ने ९ लाख करोड़ रुपये से अधिक के सरकारी ऑर्डर पूरे किए हैं। २.२० लाख से ज्यादा महिला उद्यमियों ने ९९,७१३ करोड़ रुपये से अधिक के ऑर्डर हासिल किए हैं, जबकि ४२,००० से अधिक स्टार्टअप ने ६५,६०० करोड़ रुपये से अधिक के ऑर्डर पूरे किए हैं। जेम ने ६९,००० से ज्यादा एससी/एसटी उद्यमियों को सरकारी खरीद में भाग लेने का अवसर दिया है, और उन्होंने २३,१४५ करोड़ रुपये से अधिक के ऑर्डर पूरे किए हैं।

ये उपलब्धियाँ इस बात की फिर से पुष्टि करती हैं कि जेम की भूमिका एक डिजिटल खरीद प्लेटफ़ॉर्म से कहीं ज्यादा है। यह प्लेटफ़ार्म समावेशी

विकास, उद्यमिता और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उत्प्रेरक है, जो सुनिश्चित करता है कि हर योग्य उद्यम को भारत के विकास में योगदान देने का समान अवसर मिले। कई मायनों में, जेम की यात्रा 'विकसित भारत २०४७' की आकांक्षाओं को दर्शाती है, जो प्रधानमंत्री के विकसित भारत के विजन के अनुरूप है — एक ऐसा भारत जो पारदर्शी, समावेशी, नवोन्मेयी और डिजिटल रूप से संप्रभु हो।

हम जेम के दूसरे दशक में प्रवेश कर रहे हैं, हमारा विजन इसे एक स्मार्ट, हरित और विश्व-स्तरीय प्लेटफ़ॉर्म के रूप में विकसित करना है, जो नई तकनीकों का उपयोग करता है और साथ ही हितधारकों, खासकर हमारे नवोन्मेषियों, स्टार्टअप, छोटे कारोबार, महिलाएं, युवा और छोटे शहरों और वंचित वर्गों से आने वाले उद्यमियों की भागीदारी को बढ़ाता है । भारत के सबसे सफल डिजिटल सरकारी खरीद इकोसिस्टम्स में से एक के रूप में, जेम यह दिखाता है कि कैसे तकनीक, डेटा विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उपयोगकर्ता-केंद्रित डिज़ाइन सार्वजनिक खर्च में गति, दक्षता और पैसों की सही कीमत प्रदान कर सकते हैं। पिछले दो वित्त वर्षों में, इस प्लेटफ़ॉर्म का वार्षिक जीएमवी ५ लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है, जिससे इसका कुल मूल्य लगभग २० लाख करोड़ रुपये हो गया है। इसमें अब १०,६४४ उत्पाद श्रेणियाँ और ३५० सेवा श्रेणियाँ शामिल हैं।

चाहे वह जीवन रक्षक दवाइयाँ और टीके हों, जो अस्पतालों तक तेजी से पहुँच रहे हैं, रक्षा सामग्री और ड्रोन हों, जो कुशलता से पहुँचाए जा रहे हैं, उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण हों, जो कक्षाओं को बदल रहे हैं, या विश्वसनीय अवसंरचना हो, जो गाँवों को सशक्त बना रही है - पारदर्शी और कुशल खरीद सार्वजनिक सेवाओं की उच्च गुणवत्ता और संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करती है।

इस बदलाव के सच्चे लाभार्थी भारत के नागरिक हैं। आईआईटी दिल्ली के एक अध्ययन (जुलाई-अगस्त, २०२६) में पाया गया कि जेम के माध्यम से खरीदारी से पिछले तीन वित्त वर्षों (वित्त वर्ष २०२३-२४ से २०२५-२६) में ८६,५७१.६९ करोड़ रुपये का आर्थिक लाभ हुआ, जिसमें कीमत और प्रक्रिया की दक्षता से हुई बचत शामिल है। इसी तरह, अध्ययन में जेम के १०१ उत्पादों की तुलना फ्लिपकार्ट, अमेज़न, इंडियामार्ट जैसे प्लेटफार्मों पर उपलब्ध समान वस्तुओं से की गई।

जाना चाहिए।

अभिभावकों और शिक्षकों की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वे बच्चों की रुचि और क्षमता को पहचानें तथा उन्हें खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। पढ़ाई और खेल एक-दूसरे के पूरक हैं। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन ही उत्कृष्ट शिक्षा और सफल जीवन का आधार बनते हैं।

आज जब डिजिटल दुनिया बच्चों को मैदान से दूर कर रही है, तब आवश्यकता है कि उन्हें फिर से खेल मैदानों की ओर प्रेरित किया जाए। मैदान में बिताया गया समय केवल शरीर की ही नहीं, बल्कि व्यक्तित्व, सोच और नेतृत्व क्षमता को भी मजबूत बनाता है।

खेल हमें सिखाते हैं कि हर जीत के पीछे निरंतर अभ्यास, अनुशासन और संघर्ष छिपा होता है। इसलिए अपनी प्रतिभा को पहचानिए, शासन, प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे अवसरों का भरपूर लाभ उठाइए और बस्तर ओलंपिक, सरगुजा ओलंपिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जैसे आयोजनों को अपने सपनों की उड़ान का मंच बनाइए। आज का खिलाड़ी ही कल का चौपियन, प्रदेश का गौरव और देश का भविष्य है।

लेखक सहायक जनसंपर्क अधिकारी हैं



दिव्यांग बच्चों ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा

जौनपुर। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व महंगपुर शीतला चैकिया स्थित रचना विशेष विद्यालय में गुरुवार को तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में विद्यालय के दिव्यांग बच्चे, शिक्षक एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारों के साथ यात्रा निकाली। मुख्य अतिथि जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी राजेश कुमार नायक ने रैली को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। रैली में दिव्यांग बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर रैली में शामिल हुए। रैली विद्यालय परिसर से निकलकर शीतला चैकिया धाम, धन्नेपुर चैराहा होते हुए विद्यालय परिसर में आकर समाप्त हो गयी। रैली का समापन नसीम अख्तर द्वारा किया गया। रैली के पूर्व विद्यालय परिसर में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि राजेश कुमार नायक ने कहा कि विशेष बच्चों की अक्षमताओं को नकारते हुए उनकी क्षमताओं को देखना चाहिए जिससे सामान्य तथा विशेष बच्चों में एकरूपता आ सके।

हापुड़ में मस्जिद से दो संदिग्धों को दबोचा, मेरठ लेकर गई टीम

आर्यावर्त संवाददाता

मेरठ। यूपी के हापुड़ जिले के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव शेरपुर स्थित कुरैशियान मस्जिद में शुक्रवार को एटीएस ने छापा मारकर यहां मौजूद दो संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। टीम दोनों को यहां से लेकर मेरठ रवाना हो गई। मौके पर एक संदिग्ध बाइक भी खड़ी मिली है। मस्जिद इंतजामियां कमेटी के अनुसार, दोनों युवक क्षेत्र के रहने वाले नहीं थे और बिना किसी परिचय के मस्जिद में पहुंचे थे। उन्होंने मस्जिद के बाहर बाइक खड़ी की और अंदर चले गए। सुरक्षा एजेंसी दोनों युवकों को हिरासत में लेकर पुछताछ कर रही है। हापुड़ पुलिस ने एटीएस के पहुंचने की पुष्टि की है। लेकिन इसके अलावा पुलिस के पास और कोई जानकारी नहीं है। ग्रामीणों के अनुसार दो दाड़ी और टोपी पहने मुस्लिम युवक मेरठ नंबर बाइक से सुबह यहां पहुंचे थे। दोनों की उम्र करीब 25 साल के

तिरंगा बाइक रैली निकाली गई

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत शुक्रवार को जनपद में भव्य तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ राज्यमंत्री खेल एवं युवा कल्याण गिरिश चंद्र यादव और विधान परिषद सदस्य बृजेश सिंह ‘प्रिंसु’ ने मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खड़गिया की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाकर किया।रैली में परिषदीय विद्यालयों के अध्यापक-अध्यापिकाओं के साथ बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। तिरंगा हाथों में लेकर बाइक और स्कूटी पर सवार प्रतिभागियों ने ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाते हुए देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया। सभी प्रतिभागियों ने हेलमेट पहनकर यातायात नियमों के पालन और सड़क सुरक्षा का भी संदेश दिया।रैली के समापन पर कलेक्ट्रेट स्थित विकास भवन के समीप क्रांति स्तंभ पर पुष्प अर्पित किए गए। इसके बाद सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा

पर माल्यार्पण कर स्वतंत्रता संग्राम

सेनानियों और वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई।राज्यमंत्री गिरिश चंद्र यादव ने कहा कि ‘हर घर तिरंगा’ अभियान का उद्देश्य स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के त्याग एवं बलिदान को याद करना तथा नई पीढ़ी में राष्ट्रप्रेम की भावना को मजबूत करना है। उन्होंने जनपदवासियों से अभियान में बढ़-चढ़कर भागीदारी करने और राष्ट्रध्वज का सम्मान बनाए रखने की अपील की।विधान परिषद सदस्य बृजेश सिंह ‘प्रिंसु’ ने कहा कि तिरंगे की आन, बान और शान की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने लोगों से राष्ट्रध्वज को सम्मान के साथ घर पर लगाने और उतारने के बाद सुरक्षित एवं सम्मानपूर्वक रखने की अपील की।

मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि जिलाधिकारी के नेतृत्व में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत जनपद में लगातार विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

'बेटा उठ जा... गलती मुझसे हुई'

जिला अस्पताल में बेटे के शव से लिपटी मां की चीख से हर आंख हुई नम



हो गया। भाई को पुकारते हुए बहनों की चीखें अस्पताल के माहौल को और गमगीन कर रही थीं। रिश्तेदार और पड़ोसी उन्हें संभालने की कोशिश करते रहे, लेकिन किसी के लिए भी परिवार के इस दुख को थाम पाना आसान नहीं था।

किसानों के लिए फसल बीमा योजना’ सुरक्षा कवच

जौनपुर। जिला उद्यान अधिकारी, डॉं सीमा सिंह राणा ने बताया कि जनपद के कृषकों के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित ‘पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना’ इस सीजन के लिए क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे अत्यधिक वर्षा, तापमान में उतार-चढ़ाव, सूखा या नमी के कारण फसलों को होने वाले नुकसान से किसानों को सुरक्षा प्रदान करना और उनकी कृषि आय को स्थिर रखना है।इस योजना के माध्यम से किसान अपनी बागवानी फसलों, विशेषकर केला और मिर्च का बीमा कराकर वित्तीय जोखिम को कम कर सकते हैं। योजना के तहत, केला फसल के लिए 1,50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की बीमित राशि निर्धारित की गई है, जिसके लिए किसानों को 7,500 रुपये का प्रीमियम देना होगा। इसी प्रकार, मिर्च की फसल के लिए 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की बीमित राशि पर 2,500 रुपये प्रीमियम देय है।

‘ ससुराल में तंत्र–साधना का दबाव ’ . . .कानपुर पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंची महिला, सुनाई रोंगटे खड़े करने वाली कहानी

आर्यावर्त संवाददाता

कानपुर। कानपुर में एक विवाहिता ने ससुराल वालों पर तंत्र-मंत्र के नाम पर प्रताड़ित करने, दहेज की मांग करने और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। कार्रवाई न होने से नाराज पीड़िता कमिश्नर कार्यालय आत्मदाह करने की नीयत से पहुंची। पुलिस को पहले ही इसकी सूचना मिल गई थी, जिसके चलते मौके पर भारी फोर्स तैनात रही। पीड़िता जैसे ही वहां पहुंची, पुलिसकर्मियों ने उसे समझाकर आत्मदाह से रोक लिया। पीड़िता कमिश्नर से मिलने की मांग पर अड़ी रही। काफी समझाने के बाद भी वह अपनी शिकायत पर कार्रवाई की मांग करती रही।

पीड़िता कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है। उसकी शादी 16 मार्च 2024 को पांडव नगर निवासी एक कांग्रेस नेता के बेटे से हुई थी। पीड़िता का आरोप

है कि शादी में परिवार की ओर से

काफी पैसा खर्च किया गया था। इसके बावजूद शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि ससुराल वाले उससे मायके से पैसे और सोना लाने की मांग करते थे। इसके अलावा उस पर तंत्र-मंत्र और साधना में शामिल होने का दबाव भी बनाया जाता था।

पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके ससुराल में तंत्र-मंत्र की गतिविधियां होती थीं। उसका दावा है कि परिवार के लोग रात में साधना करते थे। उस पर भी इसमें शामिल होने का दबाव बनाया जाता था। पीड़िता के मुताबिक, जब उसने इस तरह की गतिविधियों में शामिल होने से इनकार किया तो उसके साथ मारपीट की गई। उसने अपने पति पर कपड़े फाड़ने और उसे कमरे में बंद करने का भी आरोप लगाया है। पीड़िता का

वह करंट की चपेट में आ गया।

परिवार के लोगों का कहना है कि जिस स्थान पर हादसा हुआ, वहां जलभराव के बीच बिजली का पोल था। जिस समय हादसा हुआ पिता पप्पू फलमंडी में थे। बेटे की मौत की सूचना मिलने के बाद वह भी जिला अस्पताल पहुंचे। शव देखते ही उनका धैर्य जवाब दे गया। वह फूट-फूटकर रोने लगे।

रिश्तेदारों और पड़ोसियों की भीड़ परिवार को संभालने में जुटी थी। कोई मां को पकड़कर बैठा रहा तो कोई पिता और बच्चों को ढांडस देता रहा। लेकिन घर के सबसे बड़े बेटे को खोने का दर्द इतना गहरा था कि किसी की सलाह पर विचार के आंसू नहीं रोक पा रही थी। हादसे के बाद राजीव नगर मोहल्ले में भी शोक के साथ आक्रोश है।

खड़गे के अपमान पर कांग्रेस नैनिकाला विरोध मार्च



आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। हल्द्वानी में भाजपा और संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सभा मंच को अपवित्र कहकर गंगाजल से शुद्धीकरण किए जाने से आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष डा0 प्रमोद कुमार सिंह के नेतृत्व में पुष्पांजली रिस्टोर से जफराबाद थाना के सामने हाड़वे पर शुक्रवार को विरोध मार्च निकाल कर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के बाद सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव सीपी भित्तल ने कहा कि भाजपा दलितों सहित सभी समाज से नफर करती है। दलितो पर अत्याचार,

1734 ग्राम पंचायतों में लगेगें सूचना बोर्ड

जौनपुर। जिले की सभी 1734 ग्राम पंचायतों में अब सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे। इन बोर्डों पर गांव में चल रही विकास योजनाओं, स्वीकृत कार्यों, उनकी लागत, प्रगति और लाभार्थियों से संबंधित जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही, इससे कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी और पंचायत स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित होगी। इन सूचना बोर्डों के जरिए ग्रामीण यह जान सकेंगे कि उनके गांव में कौन-कौन से कार्य स्वीकृत हुए हैं, वे किस योजना के तहत संचालित हो रहे हैं और उन पर कितनी धनराशि खर्च की जा रही है। इससे संभावित अनियमितताओं पर भी अंकुर लगने की उम्मीद है। ग्रामीणों को गांव में हुए विकास कार्यों की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी ग्राम पंचायतों में सूचना बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया है।

संक्षेप

कलह से उबकर आत्महत्या किया

जौनपुर। मझिहूँ थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव में एक व्यक्ति ने परिवारिक कलह से उबकर आत्महत्या कर लिया है। उक्त गांव निवासी सुनील कुमार गौतम पुत्र कल्लन प्रसाद गौतम ने शुक्रवार की सुबह 9 बजे कीटनाशक खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। कीटनाशक खाने के कारण जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तब उसे परिजन लेकर जिला अस्पताल ले गये जहां उपचार के कुछ ही दैर बाद उसकी मौत हो गई। परिजन उसकी लाश लेकर घर चले गये।

चोरी की छह बाइक बरामद, एक गिरफ्तार

जौनपुर। कोतवाली पुलिस ने वाहन चोरी की छह मोटरसाइकिलें बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी अतुल सोनकर उर्फ बुल्ला को गिरफ्तार किया है। बरामद सभी मोटरसाइकिलें बिना नंबर प्लेट की है। पुलिस के अनुसार, 14 अगस्त की सुबह उपनिरीक्षक जयदीप कोल पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त और चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर राजासाहब पोखरे और रसूलाबाद मालगोदाम के पास करीब 4रुस15 बजे उमरपुर सुंदरनगर कॉलोनी गुलरचक निवासी अतुल सोनकर उर्फ बुल्ला को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी की छह मोटरसाइकिलें बरामद कीं। इनमें एक बाइक वढ भी है, जिसे एक जून को सदर अस्पताल जौनपुर के पास से चोरी किया गया था।

ड्यूटी में लापरवाही पर दरोगा निलंबित

जौनपुर। ड्यूटी में लापरवाही और अनुशासनहीनता के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए तेजीबाजार थाने में तैनात उपनिरीक्षक शिववदन यादव को निलंबित कर दिया। पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उपनिरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया। पुलिस के अनुसार, उपनिरीक्षक शिववदन यादव पर कर्तव्य के प्रति धुर लापरवाही, अनुशासनहीनता और स्वेच्छाचरिता के आरोप लगे थे। इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने विभागीय कार्रवाई के तहत निलंबन की कार्रवाई की। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पुलिसकर्मियों द्वारा कर्तव्य निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

खण्ड शिक्षा अधिकारी पर कार्रवाई की मांग

जौनपुर। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक शुक्रवार को संघ कार्यालय चहारसू में आयोजित हुई। बैठक में विकासखंड केराकट के खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ शिक्षकों द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों को लेकर चर्चा की गई।संघ पदाधिकारियों के अनुसार, केराकट ब्लॉक के शिक्षकों ने टक् पर अमानदारी व्यवहार करने, शिक्षिकाओं के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करने तथा जातिगत आधार पर भेदभाव किए जाने के आरोप लगाए हैं। इन शिकायतों को लेकर शिक्षक संघ ने संबंधित अधिकारी के खिलाफ निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की मांग की। संघ के संयोजक संजय कुमार सिंह ने कहा कि केराकट ब्लॉक के शिक्षकों की ओर से अधिकारी के व्यवहार को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। यदि मामले की तत्काल निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई तो शिक्षक संघ आंदोलन के लिए बाध्य होगा।प्रदेश उपाध्यक्ष डा. राजेश सिंह ने कहा कि आरोपों की निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की मांग को लेकर संघ का प्रतिनिधिमंडल जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी से मुलाकात करेगा। विजय रघुवंशी, विकास सिंह, शंभुनाथ यादव, अरुणेश कुमार, चंद्रकांत सिंह, दुर्गा यादव, ध्रुवराज यादव, रवि सिंह सहित कई शिक्षक मौजूद रहे। संचालन संघ के सहसंयोजक सत्यप्रकाश मिश्र ने किया।

उमस से बेहाल शहरवासियों को बादलों ने दी राहत की आस, सुबह से छाप बादल, बारिश का इंतजार

मेरठ। मेरठ में पिछले दो-तीन दिनों से तेज धूप और उमस भरी गर्मी ने शहरवासियों की परेशानी बढ़ा रखी है। दिनभर विपिचिपी गर्मी के कारण घरों से लेकर बाहर तक लोगों का हाल बेहाल रहा। शुक्रवार को सुबह से ही मौसम बदला हुआ नजर आया। आसमान में बादल छाप रहने और धूप का असर कम होने से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली और बारिश की उम्मीद जगी। सुबह से छाप रहे बादल, कम हुई धूप की तपिश शुक्रवार सुबह आसमान में बादलों की चादर छाई रही। कई बार धूप बादलों के पीछे छिपती रही, जिससे तेज धूप का असर कम महसूस हुआ। बादलों की लगातार आवाजही देखकर लोगों को जल्द बारिश होने की उम्मीद बनी रही। हालांकि सुबह के समय बारिश नहीं हुई। बादलों के छाप रहने के बावजूद हवा में भी अधिक होने के कारण उमस का असर बना रहा। बिना बारिश के वातावरण में विपिचिहाट महसूस होती रही। पिछले दिनों तेज धूप के साथ बूंदी उमस ने लोगों की परेशानी पहले ही बढ़ा दी थी। ऐसे में बादलों के कारण लोगों को मौसम के और बदलने की उम्मीद है। शुक्रवार सुबह बदले मौसम ने शहरवासियों को बारिश की आस जरूर दी, लेकिन बादल बरसने का इंतजार बना रहा। लोगों को उम्मीद है कि दिन में बादलों की आवाजों के साथ बारिश हो सकती है, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी।

गरीब व्यक्ति शादी अनुदान योजनान्तर्गत करें आनलाईन आवेदन

मेरठ। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी शैलेश राॅय ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की शादी अनुदान योजनान्तर्गत पात्र आवेदकों को रू0 20,000.00 (अंकर रु0 बीस हजार मात्र) का अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। शादी अनुदान हेतु आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन शादी की तिथि के 90 दिन पूर्व तथा 90 दिन पश्चात तक (उस ही वित्तीय वर्ष में) www.shadianudan.upsdc.gov.in लिंक पर जाकर किया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2026–27 में जनपद मेरठ के अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु वर्तमान में कुल 198 लाभार्थियों का बजट प्राप्त है। शादी अनुदान आवेदन हेतु अर्हता निम्न प्रकार है:- आवेदक अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) का होना चाहिए, पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है, शादी अनुदान योजनान्तर्गत आवेदक की आय शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 1,00,000/- (अंकर रु0 एक लाख मात्र) प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, आवेदक का बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए, एक आवेदक अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी अनुदान हेतु आवेदन कर सकता है, पहचान पत्र की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति, विवाह के प्रमाणपत्र की छायाप्रति, घर व कच्चा की आयु से सम्बन्धित प्रमाणपत्र, आधार कार्ड तथा आवेदक व कच्चा का फोटो होने पर शादी अनुदान हेतु आनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

विद्यार्थियों ने दिखाई देशभक्ति और रचनात्मक प्रतिभा



रंगोली प्रतियोगिताएँ तिरंगा, राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्रीय एकता की भावना पर आधारित रहीं। प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा, विचारों और देशभक्ति की भावना का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। इन आयोजनों के माध्यम से विद्यार्थियों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के गौरव, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास तथा राष्ट्रीय एकता के महत्व से जोड़ने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम के दौरान दूरदर्शन द्वारा विस्थापन, पीड़ा और सामाजिक परिस्थितियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से अवगत कराया गया। क्विज प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों, जिनमें पाँच छात्र एवं पाँच छात्राएँ शामिल होंगे, को 17 अगस्त को “हर घर तिरंगा अभियान के समापन समारोह में विश्वविद्यालय की कुलपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। सभी चयनित प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र भी प्रदान किए जाएंगे।

लोन लेने वालों के लिए बड़ी राहत! आरबीआई ला रहा है नए कड़े नियम, छिपे हुए चार्ज और मनमानी ब्याज दरों पर लगेगी लगाम

आरबीआई ने लोन की कीमत तय करने के लिए एक कॉमन फ्रेमवर्क का प्रस्ताव दिया है । इस ड्राफ्ट में कम वैल्यू वाले और माइक्रोफ़ाइनेंस लोन के लिए APR की सीमा तय करने का प्रस्ताव है । इसे विस्तार से समझते हैं



रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने लोन पर व्याज दरें तय करने के लिए एक एकसमान सिस्टम का प्रस्ताव दिया है। इसका मकसद बैंकों और दूसरे रेगुलेटेड लेंडर्स के बीच लोन देने के तरीकों को ज्यादा ट्रांसपैरेंट और एक जैसा बनाना है। इस ड्राफ्ट सिस्टम में बोर्ड से मंजूर प्राइसिंग पॉलिसी, बेंचमार्क से जुड़ी दरें और कम वैल्यू वाले लोन पर बहुत ज्यादा कीमत वसूलने से बचाने के उपाय शामिल हैं।

ये प्रस्ताव RBI की उस बड़ी कोशिश का हिस्सा है, जिसका मकसद मॉनेटरी पॉलिसी के असर को बेहतर बनाना, यह पक्का करना कि क्रेडिट की कीमत रिसक के हिसाब से तय हो और उधार लेने वालों को यह साफ तौर पर पता चले कि उनके लोन की दरें कैसे तय होती हैं। ड्राफ्ट नियम 11 सितंबर 2026 तक लोगों को राय के लिए खुले हैं और इनके 1 अप्रैल 2027 से लागू होने का प्रस्ताव है। खास बात यह है कि इस प्रस्ताव का मतलब यह नहीं है कि सभी NBFCs को फ्लोटिंग-रेट वाले लोन को किसी बाहरी बेंचमार्क से जोड़ना ही होगा। बाहरी बेंचमार्क

से जोड़ने की जरूरी शर्त कमर्शियल बैंकों के लिए फ्लोटिंग-रेट वाले रिटेल लोन और माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) को दिए जाने वाले लोन पर लागू होगी, जबकि NBFCs और कई दूसरी रेगुलेटेड संस्थाओं के पास बाहरी बेंचमार्क अपनाने या न अपनाने का फैसला करने की आजादी होगी।

आरबीआई का नया प्रस्ताव

प्रस्तावित फ्रेमवर्क के तहत, रेगुलेटेड संस्थाओं को लोन और एडवांस की कीमत तय करने के लिए बोर्ड से मंजूर एक पूरी पॉलिसी बनाए रखनी होगी। इस पॉलिसी में बताया जाएगा कि व्याज दरें कैसे तय होती हैं, कौन से बेंचमार्क लागू होंगे, स्प्रेड के हिस्से क्या होंगे, लोन की कैटेगरी क्या होंगी और कीमत तय करने की शक्तियाँ किसे दी जाएंगी। इस पॉलिसी की समीक्षा भी साल में कम से कम एक बार करनी होगी।

फिक्स्ड और फ्लोटिंग-रेट, दोनों तरह के लोन के लिए, RBI ने बेंचमार्क और रिसक-वेस्ड स्प्रेड पर आधारित एक स्ट्रक्चर का

प्रस्ताव दिया है। लेंडर को लागू बेंचमार्क से कम कीमत पर लोन देने की इजाजत नहीं होगी।

फ्लोटिंग-रेट लोन के लिए, बेंचमार्क, रीसेट फ्रॉक्वेंसी और रीसेट की तारीख लोन एग्रीमेंट में बतानी होगी। बेंचमार्क को आम तौर पर तीन महीने से ज्यादा के अंतराल पर रीसेट नहीं किया जा सकेगा। फ्रेमवर्क में यह भी प्रस्ताव है कि व्याज की कैलकुलेशन 'एक्चुअल/एक्चुअल डे-काउंट कन्वेंशन' का इस्तेमाल करके रोजाना कम होने वाले वॉलेस पर की जाए।

बेंचमार्क के ऊपर स्प्रेड में क्रेडिट रिसक प्रीमियम, ऑपरेटिंग कॉस्ट, टर्म प्रीमियम और बिजनेस स्ट्रैटेजी प्रीमियम जैसे हिस्से शामिल हो सकते हैं। अगर पूरी समीक्षा के बाद उधार लेने वाले का क्रेडिट प्रोफाइल बदलता है, तो क्रेडिट रिसक प्रीमियम में बदलाव किया जा सकता है। स्प्रेड के अन्य हिस्सों में आम तौर पर तीन साल से पहले बदलाव नहीं किया जा सकेगा, सिवाय कुछ खास मामलों के।

जिन लेंडर के पास कुल डिपॉजिट ₹1,000 करोड़ से ज्यादा है, उनके लिए प्रस्तावित इंटरनल बेंचमार्क 'मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स' पर आधारित होगा, जिसकी कैलकुलेशन घरेलू डिपॉजिट और उधार की मार्जिनल कॉस्ट के तीन महीने के मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके की जाएगी। ऐसे लेंडर को हर महीने के पहले कैलेंडर दिन इंटरनल बेंचमार्क पब्लिश भी करना होगा। आरबीआई ने कहा कि उसने बैंकों के बीच 'मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-वेस्ड लेंडिंग रेट' (MCLR) तय करने के तरीकों में अंतर देखा है, जिसके कारण ज्यादा सिद्धांतों पर आधारित फ्रेमवर्क की ओर बढ़ने का कदम उठाया गया है।

कर्ज लेने वालों पर क्या होगा असर?

बैंक ग्राहकों के लिए, सबसे बड़े बदलावों में से एक फ्लोटिंग-रेट लोन में ज्यादा

ट्रांसपेरेंसी हो सकती है। RBI का प्रस्ताव है कि कमर्शियल बैंकों द्वारा दिए जाने वाले सभी फ्लोटिंग-रेट पर्सनल या रिटेल लोन और फ्लोटिंग-रेट MSME लोन को एक बाहरी बेंचमार्क से जोड़ा जाना चाहिए। बाहरी बेंचमार्क से जुड़े लोन से RBI की पॉलिसी रेट में बदलाव का असर कर्ज लेने वालों तक बेहतर तरीके से पहुंच सकता है क्योंकि बेंचमार्क किसी एक बैंक के कंट्रोल में नहीं होता है। ड्राफ्ट के अनुसार, मौजूदा लोन को 1 अप्रैल 2029 तक एक बार की मैपिंग प्रोसेस के जरिए प्रस्तावित फ्रेमवर्क में बदलना होगा।

हालाँकि, NBFC, ऑल-इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रीजनल रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंकों को यह तय करने की छूट होगी कि वे बाहरी बेंचमार्क से जुड़े फ्लोटिंग-रेट लोन दें या नहीं। इसका मतलब है कि NBFC से लोन लेने वालों को बैंक ग्राहकों जैसा बेंचमार्क-लिकिंग सिस्टम शायद न मिले।

आरबीआई ने कम वैल्यू वाले और माइक्रोफाइनेंस लोन के लिए एक खास सुरक्षा उपाय का भी प्रस्ताव दिया है। रेगुलेटेड संस्थाओं को एनुअल परसेंट रेट पर एक स्पष्ट सीमा तय करनी होगी, जिसमें व्याज और अन्य शुल्क शामिल होंगे, और यह सुनिश्चित करना होगा कि दर बहुत ज्यादा न हो। प्रस्ताव के तहत 50,000 रुपए तक का पर्सनल लोन कम वैल्यू वाले लोन के तौर पर माना जाएगा। छोटे और सीमांत किसानों के लिए शॉर्ट-टर्म एग्रीकल्चरल लोन के मामले में, कुल व्याज और शुल्क मूल राशि से ज्यादा नहीं हो सकते। RBI ने 11 सितंबर 2026 तक ड्राफ्ट पर सुझाव मांगे हैं। प्रस्तावित निर्देश बैंकों, NBFC, कोऑपरेटिव बैंकों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और ऑल-इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर लागू होंगे, जो हर कैटेगरी पर लागू होने वाले खास प्रावधानों और छूट के अधीन होंगे।

भारतीय पैकेजिंग संस्थान में प्रोफेसर सहित 20 पदों पर नियुक्ति का मौका, इस तिथि तक करें आवेदन

नई दिल्ली, एंजेंसी। नौकरी की तलाश में जुटे लोगों के लिए भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी), दिल्ली ने विभिन्न तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों पर अस्थायी और अनुबंध के आधार पर भर्ती के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं।

आईआईपी की ओर से जारी 20 रिक्तियों में प्रोफेसर (प्रौद्योगिकी) (इमेरिटस) का 1, प्रोफेसर (प्रबंधन) का 1, एसोसिएट प्रोफेसर (प्रबंधन) का 1, असिस्टेंट प्रोफेसर (प्रबंधन) के 3, एसोसिएट प्रोफेसर (स्मार्ट और इंटेलिजेंट पैकेजिंग) का 1, असिस्टेंट प्रोफेसर (एआई/एमएल) का 1, असिस्टेंट प्रोफेसर (सतत पैकेजिंग और एलसीए) का 1, असिस्टेंट प्रोफेसर (पैकेजिंग डिजाइन) का 1, लेक्चरर (संचार कौशल) का 1, शैक्षणिक परामर्शदाता/संपर्क अधिकारी/प्लेसमेंट अधिकारी का 1, युवा पेशेवर (प्रशासन) के 2, युवा पेशेवर (इंस्ट्रुमेंटेशन) का 1, युवा पेशेवर (पुस्तकालय) का 1, लेबोरेटरी अटेंडेंट के 2 और पैकेजिंग डिजाइनर के 2 पद शामिल हैं।

इन सभी पोस्ट के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 22 अगस्त तय की गई है। ऐसे में एप्लीकेशन फॉर्म भरने के योग्य और इच्छुक उम्मीदवार तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपनी रिजस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से प्रोफेसर (प्रौद्योगिकी) (इमेरिटस) के लिए आईआईटी/एनआईटी या राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अन्य संस्थानों से सेवानिवृत्त शिक्षाविद और पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, पॉलीमर टेक्नोलॉजी/मटीरियल साइंस या संबंधित क्षेत्रों जैसे किसी प्रासंगिक विषय में पीएचडी; प्रोफेसर (प्रबंधन) के लिए मैनेजमेंट/बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन/संबंधित विषय में पीएचडी और कम से कम 10 वर्षों का टीचिंग/रिसर्च/इंडस्ट्री का अनुभव; एसोसिएट प्रोफेसर (प्रबंधन) के लिए मैनेजमेंट/संबंधित विषय में पीएचडी और कम से कम 8 वर्षों का टीचिंग/रिसर्च अनुभव; असिस्टेंट प्रोफेसर (प्रबंधन) के लिए एमबीए/एमएमएस/एमकॉम/संबंधित मास्टर डिग्री के साथ नेट/पीएचडी होनी चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर (स्मार्ट और इंटेलिजेंट पैकेजिंग) के लिए संबंधित/प्रासंगिक विषयों में पीएचडी डिग्री के साथ अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड, फर्स्ट क्लास के साथ मास्टर डिग्री, रिसर्च संस्थान/इंडस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर के बराबर एकेडमिक/रिसर्च पद पर पढ़ाने और/या रिसर्च का कम से कम आठ वर्ष का अनुभव (इसमें पीएचडी

रिसर्च का समय शामिल नहीं है)। इसके साथ ही पब्लिश हुए काम के सबूत और कितने और/या रिसर्च/पॉलिसी पेपर के तौर पर कम से कम 5 पब्लिकेशन और नेट/गेट पास होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर (एआई/एमएल) के लिए एमई/एमटेक/एमएस की डिग्री होनी चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर (सतत पैकेजिंग और एलसीए) के लिए सस्टेनेबल पैकेजिंग, सफ़ुलर इकोनॉमी, लाइफ साइकिल असेसमेंट (एलसीए), एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पैकेजिंग मटीरियल, वेस्ट मैनेजमेंट या संबंधित इंटरडिसिप्लिनरी क्षेत्रों में पीएचडी; असिस्टेंट प्रोफेसर (पैकेजिंग डिजाइन) के लिए पैकेजिंग डिजाइन, स्ट्रक्चरल पैकेजिंग,इंडस्ट्रियल डिजाइन, कंप्यूटर पैकेजिंग, सस्टेनेबल पैकेजिंग डिजाइन या संबंधित इंटरडिसिप्लिनरी क्षेत्रों में पीएचडी; लेक्चरर (संचार कौशल) के लिए इंग्लिश/कम्युनिकेशन स्टडीज/लिंग्विस्टिक्स/बिजनेस कम्युनिकेशन/जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन/संबंधित विषयों में कम से कम 55 प्रतिशत मार्क्स के साथ मास्टर डिग्री; शैक्षणिक परामर्शदाता/संपर्क अधिकारी/प्लेसमेंट अधिकारी के लिए मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन के साथ एमबीए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में होनी चाहिए।

युवा पेशेवर (प्रशासन) के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन के साथ फाइलिंग, ड्राफ्टिंग, टाइपिंग, डॉक्यूमेंटेशन, एमएस ऑफिस, डिक्टेशन, कॉलिंग और ईमेलिंग और ऑडिट डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशन व रिपोर्ट्स तैयार करने और एडिट करने का अनुभव और कुशलता होना चाहिए। युवा पेशेवर (इंस्ट्रुमेंटेशन) के लिए केमिस्ट्री/इंस्ट्रुमेंटेशन में बीएससी/एमएससी और जीसी-एमएस, एफटी-आईआर, सीएचएनएस एनालाइजर का अनुभव; युवा पेशेवर (पुस्तकालय) के लिए लाइब्रेरी साइंस/इन्फार्मेशन साइंस/डॉक्यूमेंटेशन साइंस में मास्टर डिग्री या कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ कोई समकक्ष प्रोफेशनल डिग्री; लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए साइंस के साथ कम से कम 12वीं पास और पैकेजिंग डिजाइनर के लिए एनआईटी/आईआईटी/नामी संस्थानों से प्रोडक्ट/इंडस्ट्रियल डिजाइन में एमडैस और पैकेजिंग डेवलपमेंट का अनुभव होना चाहिए।

आवेदकों की अधिकतम आयु पोस्ट के अनुसार 27 से 50 वर्ष के बीच तय की गई है। योग्य अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग, इंटरव्यू, आदि चरणों के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी पोस्ट के अनुसार 20,000 से 1,50,000 रुपए के बीच प्रति माह होगी। इसके अलावा कैंडिडेट्स को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे।

अमेरिका ने ड्रोन के इंपोर्ट पर लगाया 100% टैरिफ, निशाने पर चीन

वॉशिंगटन, एंजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रोन और उनके पार्ट्स के इंपोर्ट पर भारी टैरिफ लगाने का फैसला किया है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि अमेरिका ड्रोन और उनके कलपुर्जों के लिए विदेशी स्रोतों पर बहुत ज्यादा डिपेंड है। इस स्थिति के लिए देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को बहुत खतरा पैदा होता है।

व्हाइट हाउस के मुताबिक, ट्रंप की ओर से साइन किए गए आदेश के तहत कुछ खास आकार और क्षमताओं वाले ड्रोन पर 100 फीसदी एड वैलोरम यानी मूल्य-आधारित टैरिफ लगाया जाएगा। ये वे ड्रोन हैं जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील माना गया है। वहीं, छोटे आकार के ड्रोन पर 25 फीसदी टैरिफ लगाया जाएगा।

अमेरिका ने अपने कुछ प्रमुख सहयोगी देशों से आने वाले ड्रोन और उनके पार्ट्स के लिए अलग-अलग टैरिफ तय किए गए हैं। अमेरिकी



सरकार ने यूरोपीय संघ, जापान, लिक्टेस्टोन, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड और ताइवान से आने वाले ड्रोन और उनके पार्ट्स पर 15 फीसदी टैरिफ लगेगा। वहीं, ब्रिटेन से आने वाले ड्रोन पर 10 फीसदी एड वैलोरम टैरिफ लगाया जाएगा।

व्हाइट हाउस ने कहा कि नए टैरिफ 21 दिनों के भीतर लागू हो जाएंगे। वहीं, जो ड्रॉन्स और उसके पार्ट कम संवेदनशील माने जाते हैं,

उसपर तय किए गए टैरिफ 180 दिन बाद लागू होगा। इसी तरह, जिन प्रोडक्ट्स को पेटागन ने आदेश पर हस्ताक्षर होने के 20 दिनों के भीतर फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन (FCC) की कवर्ड लिस्ट से छूट के लिए मंजूरी दी है, उन पर भी टैरिफ 180 दिन बाद लागू होगा।

ट्रंप को क्यों लेना पड़ा ऐसा फैसला?

ट्रंप की सेहत पर झूठ बोल रहा है व्हाइट हाउस, पूर्व राष्ट्रपति के डॉक्टर ने किया दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेहत को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी का करीब 27 साल तक इलाज करने वाले कार्डियोलॉजिस्ट डॉ। जोनाथन रेनर ने ट्रंप की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर व्हाइट हाउस के दावों पर सवाल उठाए हैं। हालांकि, रेनर ने यह भी कहा है कि वह ट्रंप के डॉक्टर नहीं हैं और उन्होंने उनकी की जांच नहीं की है। 12 अगस्त को द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित एक ओपिनियन लेख में रेनर ने कहा कि पिछले एक साल के दौरान कई मौकों पर ट्रंप उन्हें ठीक नहीं दिखे। रेनर ने खास तौर पर ट्रंप के दोनों हाथों पर चोट के निशान, पेरों में सूजन और कुछ मौकों पर ट्रंप के जागते रहने के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई देने का जिक्र किया। रेनर ने राष्ट्रपति की एडवांस्ड इमेजिंग को लेकर भी सवाल उठाया और कहा कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि देश के राष्ट्रपति की सेहत कैसी है। रेनर ने यह भी साफ किया कि वह ट्रंप का इलाज नहीं कर रहे हैं और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर ही अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ट्रंप अमेरिका के सबसे ज्यादा सार्वजनिक रूप से नजर आने वाले राष्ट्रपतियों में से एक हैं। उनके स्वास्थ्य से जुड़े कुछ संकेत सार्वजनिक रूप से देखे जा सकते हैं। ऐसे में उनकी मेडिकल स्थिति को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने आनी चाहिए। रेनर की टीप्पणियों पर व्हाइट हाउस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। CNN के मुताबिक, व्हाइट हाउस ने रेनर को राजनीतिक मकसद से बिना जांच-पड़ताल के बीमारी का अंदाजा लगाने वाला बताया। प्रशासन ने यह भी कहा कि इस तरह की अटकलें मेडिकल पेशे के लिए शर्मनाक हैं। व्हाइट हाउस ने ट्रंप का बचाव करे हुए उन्हें बेहद ऊर्जवान और अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने में पूरी तरह सक्षम राष्ट्रपति बताया।

ट्रंप ने अपने आदेश में कहा कि कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लटनिक ने अमेरिका में बिना पायलट वाले एयरक्राफ्ट सिस्टम यानी UAS के इंपोर्ट के असर की जांच की थी। इस जांच में यह सामने आया कि विदेशी निर्माताओं से UAS का इंपोर्ट काफी ज्यादा है। ऐसे में अमेरिका ड्रोन तथा

उनके पार्ट्स के लिए विदेशी स्रोतों पर बहुत ही ज्यादा निर्भर हो गया है। यह ट्रंप के मुताबिक, जांच में यह भी सामने आया कि कुछ विदेशी कंपनियों के ड्रोन और उनके पार्ट्स अमेरिका की सुरक्षा और बचाव के लिए जोखिम पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा, अमेरिका का घरेलू ड्रोन

उद्योग देश की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन नहीं कर रहा है।

क्या ट्रंप का यह फैसला ‘अमेरिका फर्स्ट’ व्यापार नीति का हिस्सा?

फिलहाल, ड्रोन पर टैरिफ

लगाने का यह फैसला ट्रंप की ‘अमेरिका फर्स्ट’ व्यापार नीति का हिस्सा माना जा रहा है। कानूनी चुनौतियों और विश्लेषकों की आलोचना के बावजूद ट्रंप प्रशासन ने लगातार टैरिफ को अपनी व्यापार और विदेश नीति का अहम हथियार बनाया हुआ है। ट्रंप प्रशासन के टैरिफ को लेकर फैसले का असर ड्रोन की कीमतों, अमेरिकी बाजार में विदेशी कंपनियों की मौजूदगी और घरेलू ड्रोन मैनुफैक्चरिंग पर पड़ सकता है।

ट्रंप के इस फैसले का चीन पर कैसे पड़ेगा असर?

ट्रंप प्रशासन ने आदेश में सीधे चीन का नाम लेकर टैरिफ नहीं लगाया है, लेकिन इस फैसले का सबसे बड़ा असर चीन की ड्रोन इंडस्ट्री पर पड़ने की संभावना है। इसकी वजह यह है कि वैश्विक ड्रोन बाजार में चीनी कंपनियों, खासकर DJI, की मजबूत पकड़ है। उद्योग

संगठन AUVSI के मुताबिक चीनी कंपनियाँ कंज्यूमर ड्रोन बाजार के करीब 90% और एंटरप्राइज ड्रोन बाजार के 70% से ज्यादा हिस्से पर नियंत्रण रखती हैं। अमेरिका पहले ही चीनी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर कड़ा तरह की प्रतिबंधों का हथियार बनाया हुआ है।

भारत पर ट्रंप के इस फैसले का क्या होगा असर?

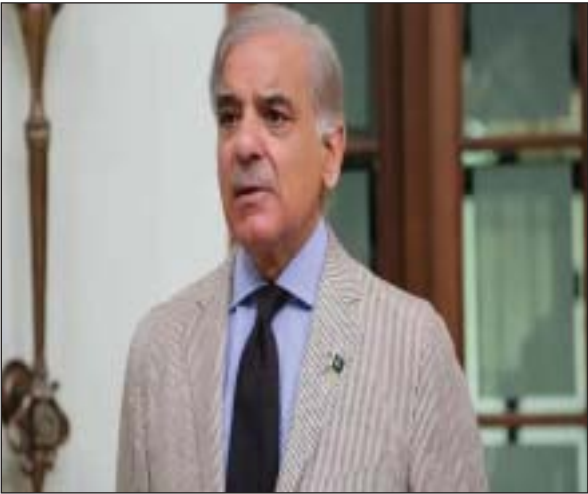
अगर अमेरिकी खरीदार चीन से ड्रोन और उनके पार्ट्स खरीदने से बचते हैं, तो भारत समेत दूसरे देशों के निर्माताओं के लिए अमेरिकी बाजार में जगह बनाने का अवसर बढ़ सकता है। खासकर सर्विलांस, एग्रीकल्चर, मैपिंग और इंडस्ट्रियल ड्रोन में भारतीय कंपनियाँ फायदा उठा सकती हैं। बता दें कि भारत पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस मैनुफैक्चरिंग में अपनी क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।

आजादी के जश्न में जल के लिए रोए शहबाज शरीफ, सिंधु पर बोले- हर एक बूंद...

इस्लामाबाद, एंजेंसी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सिंधु जल संधि को लेकर एक बार फिर भारत को गौडभूषणकी दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पानी की एक-एक बूंद रेंड लाइन है। अगर भारत ने उसके जल अधिकारों को प्रभावित करने की कोशिश की तो कड़ा जवाब दिया जाएगा।

इस्लामाबाद में गुरुवार यानी 13 अगस्त कोआजादी के जश्न से संबंधित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान शांति चाहता है। लेकिन उसकी संप्रभुता को चुनौती देने वाली किसी भी कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा।

शहबाज शरीफ ने मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष का जिक्र करते हुए एक कथित दावा किया कि पाकिस्तान ने



भारत को हराया था। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी टकराव की स्थिति में पाकिस्तान और कड़ा जवाब देगा। अपने संबोधन में शरीफ ने

कश्मीर का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने पाकिस्तान के पुराने रुख को दोहराते हुए कश्मीर को भारत के साथ व्यापक विवाद का हिस्सा बताया।

शहबाज शरीफ ने ट्रंप को सीजफायर के लिए फिर दिया धन्यवाद

शहबाज शरीफ ने मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम कराने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका की भी तारीफ की। जो उनके दावों का विरोधाभास है। अगर पाकिस्तान जीत रहा था तो उसे सीजफायर और ट्रंप को बार-बार धन्यवाद देने की जरूरत क्यों पड़ रही है। दरअसल, ट्रंप ने 10 मई 2025 को घोषणा की थी कि भारत और पाकिस्तान राजनयिक वातचीत के बाद तत्काल युद्धविराम के लिए सहमत हो गए हैं। इसके बाद शरीफ ने ट्रंप के नेतृत्व और सक्रिय भूमिका के लिए उनका धन्यवाद किया था और इस समझौते तक पहुंचने में अमेरिकी प्रयासों की सराहना की थी।

भारत ने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के दावे से किया था इनकार

हालांकि, भारत ने इस दावे को खारिज किया है। भारत का कहना है कि दोनों देशों के बीच युद्धविराम सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच हुई बातचीत से हुआ था। भारत ने इस प्रक्रिया में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की बात को स्वीकार नहीं किया है।

भारत ने सिंधु जल समझौता क्यों रोका?

सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से जल बंटवारे का आधार रही है। अप्रैल 2025 में पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत ने संधि को तत्काल प्रभाव से रोकने का फैसला किया था। इसके

बाद से पाकिस्तान लगातार इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है और संधि को कानूनी रूप से लागू बताता रहा है।

क्या है सिंधु जल समझौता?

सिंधु जल समझौता 1960 में भारत और Pakistan के बीच हुआ एक ऐतिहासिक जल-बंटवारा समझौता है, जिसकी मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी। इस समझौते के तहत सिंधु नदी प्रणाली की छह नदियों को दो हिस्सों में बांटा गया। रावी, ब्यास और सतलुज का अधिकांश जल भारत को मिला, जबकि सिंधु, झेलम और चेनाब का मुख्य उपयोग पाकिस्तान को दिया गया। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के संदर्भ में भारत लंबे समय से इस समझौते की समीक्षा की मांग कर रहा है।



परिजनों को नौकरी देने के आदेश पर SC ने हटाई रोक, कहा- सरकार की पॉलिसी पर सवाल उठाने वाले आप कौन?

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास हाई कोर्ट के एक आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के उस आदेश को रद्द कर दिया गया था, जिसके तहत पिछले साल करूर में भगदड़ में मारे गए लोगों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी दी जानी थी।

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव और अन्य लोगों को नोटिस जारी किया। बेंच ने उस पीआईएल याचिकाकर्ता से कहा, 'सरकार की पॉलिसी पर सवाल उठाने वाले आप कौन होते हैं? मान लीजिए कि हादसे में परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य मारा गया, तो क्या सरकार



को उसके बेटे या बेटों को नौकरी नहीं देनी चाहिए?' टीवीके सरकार को एक झटका देते हुए, मद्रास हाई कोर्ट ने 27 जुलाई को विजय के

उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें पिछले साल करूर में भगदड़ में मारे गए लोगों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी देने की बात कही

गई थी। कोर्ट ने कहा कि इससे ऐसी ही और भी कई मांगें उठने लगेगी। हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस सीवी

कार्तिकेयन और आर शक्तिवेल शामिल थे। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में 'कम्पैशनेट अपॉइंटमेंट' (दया के आधार पर

नियुक्ति) का इंतजार कर रहे बहुत से लोगों की जरूरतों को नजरअंदाज करना सही नहीं है। बता दें कि पिछले वर्ष 27 सितंबर को करूर में टीवीके की एक सार्वजनिक सभा के दौरान भगदड़ मची। जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया था और राजनीतिक रैलियों में भीड़ प्रबंधन तथा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। भगदड़ में मारे गए सभी लोगों के परिवारों को मुख्यमंत्री विजय ने 20-20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की थी। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई थी। इसके अलावा उन्होंने दीर्घकालिक सहायता देने का भी आश्वासन दिया था।

कैसे रोकेंगे AI वाले अपराध? : अब एआई बना साइबर अपराधियों का हथियार

नई दिल्ली, एजेंसी। देश में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध के मामलों को लेकर दर्जनों सांसदों ने चिंता जताई है। संसद सत्र में साइबर वितीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया, कितने मामले सामने आ रहे हैं, भ्रामक ऐप, डार्कनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हो रहा साइबर अपराध, सांसदों ने ऐसे कई सवाल पूछे हैं। साइबर अपराधियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को एक हथियार बना लिया है। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्रालय एवं विभिन्न एजेंसियों द्वारा साइबर क्राइम को रोकने के लिए भी 'एआई' का इस्तेमाल किया जा रहा है। सांसद अनुराग शर्मा, हैवी ईंडन, ईश्वरस्वामी के., तरुण चुघ,

अखिलेश प्रसाद सिंह, जीसी चंद्रशेखर, जोस के. मणि, डॉ. दिनेश शर्मा, बाबूभाई जैसंगभाई देसाई, डॉ. सैयद नसीर हुसैन, डॉ. राजकुमार चव्हेवाल, बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे, महूआ मोइत्रा, नारायण तातू राणे, डॉ. थोल तिरुमावलवन, सतीश कुमार गौतम, सांसद एडवोकेट गोवाल कागडा, विशाल दादा प्रकाशबाबू पाटिल, डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश, सुखचिंद्र सिंह रंधावा, डॉ. रवि कुमार, राजीव प्रताप रूडी, कीर्ति आजाद, नीरज डांगी, चमाला किरण कुमार रेड्डी, इटोला राजेंद्र, विनोद श्रीधर तावडे, रामवीर सिंह बिधुड़ी और पीसी मोहन आदि सांसदों ने साइबर क्राइम से जुड़े सवाल पूछे हैं।

बॉलीवुड के वो सितारे जिन्होंने पर्दे पर बार-बार जगाया देशभक्ति का जज्बा



बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने अपने करियर में एक नहीं, बल्कि कई देशभक्ति फिल्मों में काम किया है। कभी उन्होंने सैनिक का किरदार निभाया, तो कभी देश के लिए संघर्ष करने वाले आम नागरिक का। इन कलाकारों की फिल्मों ने दर्शकों के बीच देशप्रेम और राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत किया।

अक्षय कुमार – देशभक्ति फिल्मों का मजबूत चेहरा

देशभक्ति फिल्मों की बात हो तो अक्षय कुमार का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उन्होंने हॉलिवुड: ए सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी, एयरलिफ्ट, केसरी, गोल्ड, बेल बॉटम और सरफिरा जैसी फिल्मों में अलग-अलग तरह के देश से जुड़े किरदार निभाए हैं। उनके करियर में देश और समाज से जुड़े विषयों वाली फिल्मों की संख्या काफी ज्यादा है।

अजय देवगन – सेना से लेकर ऐतिहासिक किरदारों तक

अजय देवगन भी देशभक्ति और राष्ट्र से जुड़े विषयों पर कई फिल्मों का हिस्सा रहे हैं। द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, सिंघम, भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया और तान्हाजी जैसी फिल्मों में उनके अलग-अलग किरदार दर्शकों को पसंद आए।

सनी देओल – देशभक्ति डायलॉग्स के लिए मशहूर

देशभक्ति फिल्मों और दमदार डायलॉग्स की बात हो तो सनी देओल का नाम खास तौर पर याद किया जाता है। बॉर्डर, गदर: एक प्रेम कथा, द हीरो: लव स्टोरी ऑफ अ स्पाइ और मां तुझे सलाम जैसी फिल्मों ने उन्हें देशभक्ति सिनेमा के लोकप्रिय चेहरों में शामिल किया।

मनोज बाजपेयी – गंभीर और वास्तविक किरदार

मनोज बाजपेयी ने भी सेना, सुरक्षा और देश से जुड़े विषयों पर कई यादगार किरदार निभाए हैं। उनका अभिनय देशभक्ति की कहानियों को सिर्फ जोशीला ही नहीं, बल्कि गंभीर और भावनात्मक भी बनाता है।

प्रियंका चोपड़ा – देशभक्ति फिल्मों में भी दमदार मौजूदगी

अभिनेत्रियों की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा ने जय गंगाजल, मेरी कॉम और द स्काई इज पिंक जैसी फिल्मों में अलग-अलग मजबूत किरदार निभाए हैं। मेरी कॉम में उन्होंने भारत की महिला



फिल्मोग्राफी में ऐसे किरदार भी रहे हैं जो देश और समाज से जुड़े संवेदनशील मुद्दों को सामने लाते हैं।

कौन है सबसे आगे?

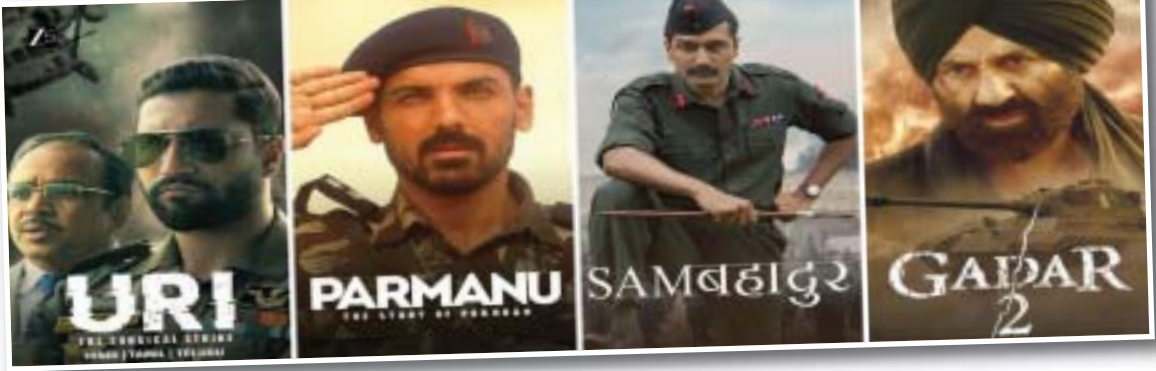
अगर देशभक्ति फिल्मों की पहचान और संख्या दोनों को मिलाकर देखें, तो अक्षय कुमार, अजय देवगन और सनी देओल जैसे अभिनेता इस मामले में सबसे प्रमुख नामों में नजर आते हैं। वहीं अभिनेत्रियों में भी कई सितारों ने सेना, खेल, इतिहास और राष्ट्र से जुड़े किरदार निभाकर अपनी अलग पहचान बनाई है।

बॉलीवुड में देशभक्ति का सिनेमा सिर्फ युद्ध और सीमा तक सीमित नहीं रहा। समय के साथ इसमें खेल, इतिहास, आतंकवाद, सामाजिक जिम्मेदारी और आम भारतीय के संघर्ष की कहानियां भी शामिल होती गई हैं। यही वजह है कि देशभक्ति वाली फिल्मों का क्रेज आज भी कायम है।

बॉक्सर की भूमिका निभाकर देश के खेल और महिला शक्ति की कहानी को पर्दे पर पेश किया।

करीना कपूर – सैनिक परिवार की कहानी से जुड़ा किरदार

करीना कपूर भी देशभक्ति से जुड़े सिनेमा का हिस्सा रही हैं। बजरंगी भाईजान और तलाश जैसी फिल्मों से अलग उनकी



देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी तक सीमित नहीं है। बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में बनी हैं, जो देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, सैनिकों का साहस और भारत के प्रति सम्मान की भावना को पर्दे पर उतारती हैं। अगर इस समय आपका मूड भी कुछ ऐसी ही फिल्म देखने का है, तो ये फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में शामिल हो सकती हैं।

1. बॉर्डर

भारतीय सेना की बहादुरी और युद्ध के दौरान सैनिकों के संघर्ष को दिखाने वाली यह फिल्म देशभक्ति सिनेमा की यादगार फिल्मों में गिनी जाती है। फिल्म के डायलॉग और गाने आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं।

2. उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक

कारगिल युद्ध पर आधारित यह फिल्म कई

अगर आपको देशभक्ति के साथ जबरदस्त एक्शन पसंद है, तो यह फिल्म अच्छा विकल्प है। फिल्म भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी से प्रेरित है और इसमें सैनिकों के साहस की प्रमुखता से दिखाया गया है।

3. शेरशाह

कैप्टन विक्रम बत्रा की जिंदगी और कारगिल युद्ध में उनके अदम्य साहस पर आधारित यह फिल्म इमोशन और देशभक्ति दोनों से भरपूर है। फिल्म यह भी दिखाती है कि देश की रक्षा करने वाले जवानों के पीछे उनकी अपनी भावनाओं और रिश्तों की भी एक दुनिया होती है।

4. एलओसी: कारगिल

कारगिल युद्ध पर आधारित यह फिल्म कई

सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को सामने लाती है। अगर आपको युद्ध और सेना से जुड़ी कहानियां पसंद हैं, तो इसे भी वॉचलिस्ट में रखा जा सकता है।

5. मेजर

यह फिल्म मेजर सदीप उन्नीकृष्णन की जिंदगी पर आधारित है। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान उनकी बहादुरी और बलिदान की कहानी फिल्म को भावनात्मक बना देती है।

देशभक्ति फिल्मों की खास बात इन फिल्मों को देखने के बाद सिर्फ जोश ही नहीं आता, बल्कि यह एहसास भी होता है कि देश की सुरक्षा के लिए जवान किस तरह अपने परिवार और निजी जिंदगी से दूर रहकर जिम्मेदारी निभाते हैं। यही वजह है कि देशभक्ति पर बनी फिल्में हर पीढ़ी के दर्शकों से जुड़ती हैं।

देशभक्ति वाली फिल्मों का बदलता अंदाज : जब पर्दे पर कहानी के साथ जागता है देशप्रेम



बॉलीवुड में देशभक्ति पर फिल्में बनाने का चलन नया नहीं है। हिंदी सिनेमा ने अलग-अलग दौर में सैनिकों की बहादुरी, देश के लिए बलिदान, आजादी की लड़ाई और आम नागरिकों के भीतर छिपे राष्ट्रप्रेम को पर्दे पर उतारा है। खास बात यह है कि समय के साथ देशभक्ति फिल्मों का अंदाज भी काफी बदला है एक दौर था जब देशभक्ति फिल्मों में सीमा पर लड़ते जवान, तिरंगा और देश के लिए कुर्बानी मुख्य केंद्र हुआ करते थे। उपकार, हकीकत और शहीद जैसी फिल्मों ने दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ा। इन फिल्मों में देशप्रेम को सिर्फ संवादों से नहीं, बल्कि किरदारों के संघर्ष और बलिदान से दिखाया गया।

बाद के दौर में बॉलीवुड ने देशभक्ति को एक्शन और मनोरंजन के साथ जोड़ना शुरू किया। बॉर्डर, एलओसी कारगिल, उरी: द सर्जिकल

हालांकि, देशभक्ति फिल्मों के सामने एक चुनौती भी है। दर्शकों का एक बड़ा वर्ग अब सिर्फ जोश और बड़े-बड़े संवादों से प्रभावित नहीं होता। वह मजबूत कहानी, वास्तविक किरदार और तथ्यों के कबीर रहने वाली फिल्में देखना चाहता है। यही वजह है कि आज के दौर में ऐसी फिल्मों की मांग बढ़ रही है जिनमें देशभक्ति के साथ कहानी और मनोरंजन का संतुलन भी हो।

कुल मिलाकर, बॉलीवुड की देशभक्ति फिल्मों ने समय के साथ अपना रूप जरूर बदला है, लेकिन उनका मूल भाव आज भी वही है— देश के प्रति सम्मान, समर्पण और जिम्मेदारी। यही वजह है कि जब पर्दे पर तिरंगा लहराता है और बैकग्राउंड में देशभक्ति की धुन बजती है, तो सिनेमाघर में बैठे दर्शकों के भीतर भावनाओं की एक अलग ही लहर दौड़ जाती है।

